International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 02 February- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

भारत में कृषि का व्यावसायीकरण और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव

डॉ0 केशरी नन्दन मिश्रा
एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश, भारत।

कृषि के व्यावसायीकरण का अर्थ है कि किसानों द्वारा कृषि फसलों और वस्तुओं का उत्पादन बाजार में बिक्री के लिए किया जाता है न कि अपने उपभोग के लिए। कृषि के व्यावसायीकरण से हमारा तात्पर्य परिवार के उपभोग के बजाय बाजार में बिक्री के लिए कृषि फसलों के उत्पादन से है। निर्वाह खेती से हटकर बाजारोन्मुख कृषि की ओर बढ़ना और कृषि के व्यावसायीकरण के माध्यम से पारंपरिक खाद्य फसलों की खेती से नकदी फसलों की ओर स्थानांतरण को ग्रामीण परिवारों की खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति में सुधार के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। भारत में तीन प्रमुख प्रकार के कृषि व्यावसायीकरण थे। व्यावसायीकरण का पहला रूप बागान कृषि, विशेष रूप से बंगाल के उत्तरी जिलों के चाय बागान से जुड़ा था। दूसरे प्रकार के व्यावसायीकरण को 'निर्वाह व्यावसायीकरण' या 'पटसन चरण' के रूप में जाना जाने लगा। व्यावसायीकरण के इस जूट संस्करण के तहत, न्यूनतम निर्वाह स्तर की तलाश में किसानों ने गहन नकदी फसलों की ओर रुख किया, मुख्य रूप से 19 वीं सदी के अंत और 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में जूट। कृषि पारिस्थितिकी में तेजी से जनसंख्या वृद्धि जो पहले से ही उच्च जनसंख्या दबाव में है, विकास नीति के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह जटिल कृषि पारिस्थितिकी में और भी बड़ी चुनौती बन जाती है जहां तेजी से कृषि विस्तार के लिए नई तकनीक उपलब्ध नहीं है। परिवहन और विदेशी व्यापार के विकास ने तंबाकू, मूंगफली और आलू जैसी कई नई फसलों की शुरुआत की, जबकि बाद के चरण में, कंपनी की वाणिज्यिक आवश्यकताओं ने इसे नील, जूट, चाय और की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया। कॉफ़ी। खाद्य सुरक्षा और पोषण नीति के हस्तक्षेप आम तौर पर चुनिंदा उपायों पर निर्भर करते हैं। फिर भी हालिया साहित्य . के महत्व पर जोर देता है

भारतीय कृषि उपज की इस बढ़ती हुई मांग ने व्यावसायीकरण की प्रवृत्ति के प्रसार में मदद की। विशेष फसलों में विशेषज्ञता वाले देश के विभिन्न हिस्सों के साथ वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्र का विस्तार किया जाने लगा। फिर भी एक अन्य योगदान कारक भू-राजस्व के नकद मूल्यांकन के रूप में मुद्रा अर्थव्यवस्था की शुरूआत और नकद किराए द्वारा किराए के प्रतिस्थापन के रूप में था। सामान्य फसलों की खेती अब लाभदायक नहीं थी और किसान को बाहरी बाजार, भारतीय या विदेशी के लिए उच्च कीमत वाली फसल उगानी पड़ती थी। नकदी फसलों की खेती में तेजी से वृद्धि का एक मूल कारण यह था कि इस तरह के विकास का भारत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया था। वाणिज्यिक क्रांति का भारतीय ग्रामीण समाज के सामाजिक-आर्थिक ढांचे पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। यह अतीत के साथ एक गंभीर विराम लेकर आया क्योंकि अब यह आवश्यक नहीं रह गया था कि एक गाँव या यहाँ तक कि एक पूरे क्षेत्र में खाद्यान्न और जीवन की अन्य आवश्यकताओं में आत्मनिर्भर हो। वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में यह वृद्धि, हालांकि, इन फसलों के तहत क्षेत्र में एक समान वृद्धि का संकेत नहीं देती है। केवल किसान ने ही अपनी बेहतर गुणवत्ता और सिंचित भूमि को अपनी खेती के लिए समर्पित किया। जनसंख्या के दबाव को देश की कृषि प्रगति में उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए था। पारंपरिक कृषि का

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 02 February- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

बढ़ा हुआ बाजार एकीकरण विकास की ओर उन्मुख विकास रणनीति का हिस्सा है। स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण विशेषज्ञता के माध्यम से लाभ का वादा करता है। इस प्रकार कृषि का व्यावसायीकरण, कुछ क्षेत्रों में विशेष फसलों के उत्पादकों को मिलने वाले लाभों के बावजूद, देश में गेहूं और चावल के निर्यात में वृद्धि, देश में खाद्य भंडार को कम करने, अनाज की कीमतों में वृद्धि करके देश में समग्र खाद्य स्थिति में गिरावट आई। ज्वार और बाजरा जैसे घटिया अनाज की खेती को हतोत्साहित करना जिसके लिए कोई तैयार निर्यात मांग नहीं थी। इस संदर्भ में व्यावसायीकरण के कई पहलू हो सकते हैं। सामान्यतया, यह किसी व्यक्ति या परिवार के अन्य लोगों के साथ आर्थिक लेन-देन का वर्णन करता है। ये नकद और वस्तु दोनों रूप में हो सकते हैं, बाद वाले कई पारंपरिक समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेन-देन कृषि उपज से संबंधित हो सकते हैं, यह दर्शाता है कि खेत के उत्पादन का एक निश्चित अनुपात निर्वाह के लिए नहीं बल्कि बिक्री के लिए उत्पादित किया जाता है। वे इनपुट से भी संबंधित हो सकते हैं, यह दर्शाता है कि एक खेत की उत्पादन तकनीक बाहरी इनपुट पर कुछ हद तक निर्भर करती है। पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त भोजन की खपत का गरीबी से गहरा संबंध है, और गरीबों के बीच बढ़ती आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अधिक भोजन पर खर्च होने की उम्मीद है। यदि कम आय वाले फ़ैनर्स और भूमिहीन मजदूर निर्वाह से नकदी फसल उत्पादन में बदलाव से उत्पन्न आर्थिक अधिशेष के कम से कम हिस्से पर कब्जा कर लेते हैं, और यदि इन लोगों का एक हिस्सा कुपोषित है, तो कोई उम्मीद करेगा कि पोषण की स्थिति में सुधार होगा।

कृषि व्यावसायीकरण में ब्रिटिश शासन और त्वरण

भारत में कपास, जूट और गन्ना जैसी व्यावसायिक फसलें बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शासन से पहले ही उगाई जाती थीं। सही मायने में, व्यावसायीकरण ब्रिटिश सरकार के तहत ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नीति थी। भारत का व्यावसायीकरण का अनुभव, इस प्रकार, उन्नीसवीं शताब्दी में भूमि अधिकारों के कानूनी अधिकार, किसानों के भेदभाव, नकद में राजस्व लेनदेन, ऋण का उपयोग, नकदी-फसलों में बदलाव, परिवहन के विकास, सिंचाई आदि के साथ शुरू होता है। नाडकर्णी (1979) का तर्क है कि भारत में व्यावसायीकरण कृषि के वास्तविक पूंजीवादी विकास के बिना हो रहा है। उपनिवेशों के मुनाफे में वृद्धि पर केंद्रित कृषि गतिविधियों के पीछे का मकसद आत्मनिर्भरता से व्यावसायीकरण में स्थानांतरित हो गया। नतीजतन, नकदी फसलों की उपज में वृद्धि हुई, लेकिन इससे किसानों को कोई मदद नहीं मिली। किसान अब खाद्य फसलों के बजाय बड़े पैमाने पर नकदी फसलों का उत्पादन कर रहे थे, जो अंततः ब्रिटिश उद्योगों के लाभ के लिए उपयोग किए गए थे। इन नकदी फसलों में कपास, जूट, तिलहन, गन्ना, तंबाकू आदि शामिल हैं।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में कृषि

भारत की कृषि-पारिस्थितिकी सेटिंग की विविधता, उच्च जैव-विविधता और श्रम की अपेक्षाकृत कम लागत एक वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में कृषि प्रतिस्पर्धा के लिए क्षमता प्रदान करती है। जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों की प्रकृति में कृषि आर्थिक क्षेत्रों में अद्वितीय है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के पिछले अध्ययनों ने मॉडल इनपुट और मॉडल विनिर्देश में अंतर से उत्पन्न कीमतों, उत्पादन और व्यापार जैसे परिणामों में पर्याप्त अंतर

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 02 February- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

की सूचना दी है। कृषि विकास के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/विस्तार कार्यक्रमों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। निजीकरण, विनियमन और वैश्वीकरण के संबंध में नीति समायोजन के बाद बदलते आर्थिक परिवेश के संदर्भ में परिवर्तन आवश्यक हैं, विस्तार प्रणाली की अधिक दक्षता और प्रभावशीलता की मांग करते हुए। बढ़ते वैश्वीकरण का एक अन्य महत्वपूर्ण निहितार्थ घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों के लिए उत्पाद और उत्पादों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता से संबंधित है। इसका मतलब यह होगा कि उत्पादन को वास्तविक रूप से तेजी से बदलती उत्पाद मांग के अनुरूप होना चाहिए।

व्यावसायीकरण और कृषि परिवर्तन

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ, एक कृषि संकट की शुरुआत के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्र में किसानों का प्रवेश हुआ, जैसा कि गांधीजी के नेतृत्व में चंपारण और कालरा अभियानों के दौरान हुआ था। परिणामस्वरूप, मिट्टी के काश्तकार ने भारतीय समाज के छात्रों का काफी ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। बंबई में जी. कीटिंग्स और हेरोल्ड मान, मद्रास में गिल्बर्ट स्लेटर और पंजाब में ई.वी. लुकास ने विशेष गांवों और सामान्य कृषि समस्याओं का गहन अध्ययन शुरू किया। इन जांचों के परिणामों ने बहुत रुचि पैदा की और अभी भी आगे के अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया । खनन, निर्माण, वाणिज्य और परिवहन में लगी कृषि आबादी की भारी प्रधानता को देखते हुए, इसकी अनदेखी किए जाने की संभावना नहीं है; और कम से कम दक्षिणी भारत में, जिसकी कोई कोयला खदान नहीं है और बंबई में कपास निर्माण और बंगाल में जूट जैसे कोई महान उद्योग नहीं हैं । दुबे के अनुसार: एक क्षेत्रीय और साथ ही सामाजिक, आर्थिक और अनुष्ठान इकाई, गांव एक अलग और विशिष्ट इकाई है। इस बस्ती के निवासी अपनी कॉर्पोरेट पहचान को पहचानते हैं, और इसे अन्य लोगों द्वारा पहचाना जाता है। उनमें अपने स्वयं के बसावट स्थल के प्रति लगाव की भावना का होना असामान्य नहीं है ।

भारतीय किसानों के जीवन स्तर की वर्तमान स्थिति

एनसीएईआर के अनुसार, 2016 में भारत की मध्यम वर्ग की आबादी 267 मिलियन होगी। आगे, 2025-26 तक भारत में मध्यम वर्ग के परिवारों की संख्या 2015-16 के स्तर से दोगुनी से अधिक 113.8 मिलियन परिवारों या 547 मिलियन व्यक्तियों तक पहुंचने की संभावना है। . एक अन्य अनुमान ने भारतीय मध्यम वर्ग को 2030 तक 475 मिलियन लोगों की संख्या के रूप में रखा। यह अनुमान है कि 2013 और 2030 के बीच औसत वास्तविक मजदूरी चौगुनी हो जाएगी। कृषि में प्रगति का एक महत्वपूर्ण पहलू आयातित खाद्यान्न पर इसकी महत्वपूर्ण निर्भरता के उन्मूलन में इसकी सफलता है। . भारतीय कृषि ने लगातार सूखे और भोजन की कमी की चपेट में आने के युग से कृषि वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण निर्यातक बनने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसान हमारे देश की रीढ़ है इसलिए यदि किसान स्वस्थ है तो पूरा देश स्वस्थ है मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था, किसान पर निर्भर लोगों की आजीविका। सिचुएशन असेसमेंट ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि 40 प्रतिशत से अधिक किसान वैकल्पिक अवसर उपलब्ध होने पर कृषि छोड़ना चाहेंगे। कृषि में भीड़ होती जा रही है और यह नियमित रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रोजगार के अभाव में,

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 12 Issue 02 February- 2022
ISSN: 2249-7382 | Impact Factor: 8.018|
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

ग्रामीण आबादी, विशेषकर युवा, बेहतर अवसरों और आय की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। 2020 तक, 15-34 आयु वर्ग के लोग भारत की जनसंख्या का 34 प्रतिशत हिस्सा बन जाएंगे; वर्तमान में, भारत के 70 प्रतिशत से अधिक युवा ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी ऊर्जा और उत्साह को उन तरीकों से इस्तेमाल करने की जरूरत है जो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बदलते हैं। लेकिन कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की बढ़ती संख्या को स्वयं अवशोषित नहीं कर पाएगी।

निष्कर्ष

कृषि क्षेत्र ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है जिसके चारों ओर सामाजिक-आर्थिक विशेषाधिकार और अभाव घूमते हैं, और इसकी संरचना में किसी भी बदलाव का सामाजिक समानता के मौजूदा पैटर्न पर एक समान प्रभाव पड़ने की संभावना है। कृषि के इस बदलते परिदृश्य में आय को बदलने की जरूरत है। कृषि जल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है जो कुल खपत का लगभग 80% हिस्सा है। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता के बाद से ही जल संसाधनों का विकास सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, औद्योगिक और विभिन्न विविध उपयोगों जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है। व्यावसायीकरण के लाभ के बावजूद, किसानों ने नकदी फसलों के बारे में बहुत कुछ नहीं सीखा है। आज तक किसान अपने फसल पैटर्न में पारंपरिक हैं। उन्होंने धान की खेती के प्रति अपने रूढ़िवादी दृष्टिकोण को नहीं बदला है। उन्हें खाद्य फसलों से नकदी फसलों की ओर अपना विचार बदलने के लिए उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। बैंकिंग, परिवहन और बाजार जैसे बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना चाहिए। किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक किया जाए। प्रीमियम बहुत कम होना चाहिए और बीमा का कवरेज विशिष्ट फसलों तक सीमित नहीं होना चाहिए।

References

- Acharya, S.S., 1998. "Agricultural price policy and development: some facts and emerging issues", *Indian Journal of Agricultural Economics*, vol. 52, No. 1: 1-47.
- Burmeister; Larry L. 2000. 'Dismantling Statistics East Asian Agricultures? Global Pressures and National Responses', *World Development*, 28(3), 443-455.
- Chopra, Kanchan 2005. 'Price and Non-Price Reform in Indian Agriculture: A Reexamination and Some Reflections', *Indian Journal of Agricultural Economics*, 60(1), 1-23.
- Ghuman, R. S. 2005 'Rural Non Farm Employment Scenario: Reflections from Recent Data in Punjab', *Economic and Political Weekly*, 40(41), 4473-4480.
- Indian Agriculture in Brief 2000: *Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi*
- Kaur, R. (2011). Indebtedness among farmers. Twenty First Century Publications, Patiala, 92
- Varadharajan, S (2015) India may need to import 10 million tonnes of pulses, The Hindu, Business and Agri-Business, November 1st 2015.